भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-131
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में निवेश

131. **श्री दिलीप शइकीया:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 सहित विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के अंतर्गत यथा अधिदेशित कुल छह प्रतिशत निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार प्रमुख मानव विकास सूचकांकों और उनमें प्रति व्यक्ति व्यय में सुधार लाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई उपाय कर रही है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का स्पष्ट रूप से समर्थन और परिकल्पना की गई है। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं ताकि इसे जल्द से जल्द जीडीपी के 6% तक पहुँचाया जा सके। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को एनईपी 2020 के अनुरुप बनाया गया है।

जहां तक शिक्षा मंत्रालय का संबंध है, बजट आवंटन में 99,311.52 करोड़ रुपये **(**2020-21) से 1,21,117.77 करोड़ रुपये **(**2024-25) तक की वृद्धि हुई है, जो लगभग 21.95% की वृद्धि है।

(ख) और (ग): भारत सरकार समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसके द्वारा कई लक्षित योजनाएं शुरू की गई हैं जिनका उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करना, सामाजिक सुरक्षा, आय सृजन और आजीविका के विकल्प प्रदान करना और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में आबादी के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

सरकार द्वारा लक्षित पहलों में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जन धन, आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, पीएम-मुद्रा योजना, सौभाग्य, स्टार्ट-अप इंडिया आदि शामिल हैं, ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाया जा सके। इसके अलावा, वित्तीय सहायता के संबंध में कुछेक उपायों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम-मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी पहलें शामिल हैं, जिन्हें लागू किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को भी लागू कर रहा है।

इन पहलों के साथ, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार गरीबी उन्मूलन, सभ्य कार्य प्रदान करने, आर्थिक विकास, जलवायु कार्रवाई और भूमि पर जीवन के संबंध में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार, देश के लिए समग्र एसडीजी स्कोर 2023-24 के लिए 71 है, जिसमें 2020-21 में 66 और 2018 में 57 (बेसलाइन रिपोर्ट) की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है। लक्ष्य 3 - अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के तहत, समग्र स्कोर 2018 में 52 से 2023-24 में 77 तक काफी हद तक सुधरा है; लक्ष्य 4 - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तहत, समग्र स्कोर 2018 में 58 से बढ़कर 2023-24 में 61 हो गया; और लक्ष्य 8 - सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के तहत, समग्र स्कोर 2018 में 65 से बढ़कर 2023-24 में 68 हो गया। सभी राज्यों ने समग्र स्कोर में सुधार दिखाया है।

इन उपायों का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, मानव विकास सूचकांक में सुधार करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और समावेशी शैक्षिक विकास को सक्षम बनाना है।

*****